International Journal of Arts, Humanities and Social Studies 2025; 7(2): 298-306

International Journal of Arts, Humanities and Social Studies and Social Studies

ISSN Print: 2664-8652 ISSN Online: 2664-8660 Impact Factor: RJIF 8.31 IJAHSS 2025; 7(2): 298-306 www.socialstudiesjournal.com Received: 06-08-2025 Accepted: 05-09-2025

डॉ. चन्द्रा सत्या प्रकाश

राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत।

भारत की राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन राजनीति का महत्व : एक विश्लेषणात्मक अवलोकन

चन्द्रा सत्या प्रकाश

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26648652.2025.v7.i2d.315

सारांश

गठबंधन शब्द लैटिन शब्द कोएलिटियो से लिया गया है जिसका अर्थ है एक साथ बढ़ना। जब कई राजनीतिक दल चनाव पूर्व सरकार बनाने की इच्छा या चुनाव पश्चात सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं और एक आम सहमति वाले कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हम इस प्रणाली को गठबंधन राजनीति या गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन एक सहकारी व्यवस्था को दर्शाता है जिसके तहत अलग-अलग राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दलों के साथ कई उद्देश्यों से प्रभावित होकर गठबंधन करता है। यह एक बहदलीय सरकार की परिघटना है जहाँ कई अल्पसंख्यक दल सरकार चलाने के उद्देश्य से हाथ मिलाते हैं। गठबंधन तब बनता है जब सदन में कई अलग-अलग समृह अपने व्यापक मतभेदों को भुलाकर एक साझा मंच पर हाथ मिलाकर बहमत बनाने के लिए सहमत होते हैं। गठबंधन प्रणाली का अंतर्निहित सिद्धांत विशिष्ट हितों के अस्थायी संयोजन के सरल तथ्य पर आधारित है। गठबंधन की राजनीति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील मामला है, क्योंकि गठबंधन के घटक और समृह विघटित हो जाते हैं और नए समृह बन जाते हैं। गठबंधन राजनीति का मूल मंत्र समझौता है, तथा इसमें कठोर हठधर्मिता का कोई स्थान नहीं है। गठबंधन समायोजन का उद्देश्य सत्ता पर कब्ज़ा करना है। आधुनिक चुनाव प्रक्रिया में कई राजनीतिक दल समान राजनीतिक विचारधारा, साझा राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक महत्वकांक्षा, राजनीतिक अवसरवादिता, राजनीतिक लाभ इत्यादि के आधार पर गठबंधन राजनीति में शामिल होता है। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात गठबंधन राजनीति होती रही है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1967 तक कांग्रेस पार्टी का केंद्र और सभी राज्यों में सरकारें थी। लेकिन 1967 से कई राज्यों में अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी सरकारें बनायी। क्षेत्रीय दलों के उभार ने कांग्रेस को कई राज्यों में चुनौती दिया जिसके परिणामस्वरूप पहली बार 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी थी। हालाँकि जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में बनी सरकार 1980 में गिर गई थी। इस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं है कि इस दौर में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य से ग़ायब हो गई। लेकिन इस दौर में कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मज़बूती से उभार ने राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन सरकार की मजबूरी को बढ़ा दिया। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन की पुन: सरकार बनी। 1989 से 2014 तक, आम चुनावों में किसी भी एक दल को बहमत नहीं मिला। 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले बहमत के आँकड़ों को पार किया था। भाजपा के इस उपलब्धि से राजनीतिक विश्लेषकों ने मान लिया था कि एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में एकदलीय शासन का वर्चस्व स्थापित हो गया है। 2014 से पहले, भारत ने आखिरी बार 1984 में लोकसभा में एकदलीय बहमत देखा था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 400 से अधिक सीटें जीती थीं। लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दस साल के एकदलीय शासन का अंत कर दिया है। भाजपा संसद में अपने बल पर सरकार बनाने के लिए बहमत का आंकड़ा पार करने में विफल रही है। वर्तमान समय में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार है लेकिन इस सरकार की बुनियाद जनता दल (यूनाइटेड), तेलगु देशम पार्टी, शिवसेना (शिंदे) के समर्थन पर टिकी हुई है। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से गठबंधन राजनीति का महत्व बढ गया है।

कूटशब्द : राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय पार्टी, एकदलीय शासन, क्षेत्रीय उभार, क्षेत्रीय दल, गठबंधन राजनीति, गठबंधन समायोजन।

प्रस्तावना

गठबंधन एक राजनीतिक व्यवस्था को संदर्भित करता है, जिसमें कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, जबिक किसी भी एक दल को विधायिका में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। भारत में गठबंधन सरकार के लिए योगदान देने वाले कारक: बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय विविधता और राज्य दलों का उदय, सत्ता विरोधी कारक आदि। भारत में गठबंधन सरकारें दो मुख्य मार्गों से बन सकती हैं: चुनाव-पूर्व गठबंधन: पार्टियाँ चुनाव से पहले गठबंधन बनाती हैं, तथा मतदाताओं के सामने एकजुट मोर्चा प्रस्तुत करती हैं। चुनाव-पश्चात गठबंधन: पार्टियां चुनाव परिणामों के बाद सरकार बनाने के लिए बातचीत करती हैं, अक्सर तब जब कोई भी चुनाव-पूर्व गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता है। चुनाव-पूर्व गठबंधन एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल चुनाव से पहले एक-दसरे का सहयोग और समर्थन करने के लिए सहमत होते हैं।

Corresponding Author: डॉ. चन्द्रा सत्या प्रकाश राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक

राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत। यह गठबंधन आमतौर पर वोटों को एकजुट करके, वोटों के बंटवारे को रोककर और आम विरोधियों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाकर अपनी जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। चुनाव-पूर्व गठबंधन काफी फायदेमंद होता है क्योंकि यह पार्टियों को एक संयुक्त घोषणापत्र के आधार पर मतदाताओं को लुभाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है (ब्लारेल 2019, पृष्ठ संख्या-585)। चुनाव-पश्चात गठबंधन एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सहयोग करने और गठबंधन बनाने के लिए सहमत होते हैं। इस प्रकार का गठबंधन आमतौर पर तब बनता है जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, जिससे शासन करने के लिए आवश्यक संख्या बल प्राप्त करने हेतु सहयोग आवश्यक हो जाता है। चुनाव-पश्चात गठबंधन का उद्देश्य घटकों को राजनीतिक सत्ता साझा करने और सरकार चलाने में सक्षम बनाना है।

गठबंधन अक्सर हितों और क्षेत्रों की एक व्यापक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे संभावित रूप से अधिक समावेशी नीतियों और कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त होता है । गठबंधन साझेदार एक-दूसरे पर नियंत्रण रख सकते हैं, जिससे अधिनायकवाद और जल्दबाजी में लिए गए नीतिगत निर्णयों का जोखिम कम हो सकता है। गठबंधन के लिए बातचीत और समझौते की आवश्यकता होती है, जिससे संभवतः अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत नीतियां बन सकती हैं। गठबंधन सरकारों के परिणामस्वरूप लोकसभा में अधिक जीवंत और ठोस बहस होती है, तथा सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। गठबंधन सरकारों में अक्सर क्षेत्रीय दल शामिल होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाती है और शासन के प्रति विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपना लिया जाता है (कुमार 2017, पृष्ठ संख्या-4) । गठबंधन सहयोगियों के अलग-अलग हितों के कारण अक्सर मतभेद और सरकारी अस्थिरता हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1998 में पहली एनडीए सरकार का मात्र 13 महीने बाद ही गिर जाना । गठबंधन सहयोगियों के बीच आम सहमति की आवश्यकता के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर वामपंथी दलों द्वारा यूपीए-I सरकार से समर्थन वापस लेना । गठबंधन की गतिशीलता में बार-बार होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप दीर्घकालिक रणनीतियों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। गठबंधन बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को अपनी मूल विचारधाराओं को कमजोर करना पड़ सकता है। गठबंधन में क्षेत्रीय दल अक्सर राज्य-विशिष्ट लाभ, क्षेत्रीय सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों के आवंटन आदि के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाते हैं। गठबंधन की गतिशीलता विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में । उदाहरण के लिए, तृणमूल कांग्रेस के विरोध के कारण 2011 से तीस्ता जल समझौते पर निर्णय रुका हुआ है

भारत में गठबंधन सरकारें कोई नई बात नहीं हैं। दुनिया के सबसे बड़े गठबंधनों में से कुछ, जिनमें छह से एक दर्जन पार्टियां शामिल हैं, विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र में गठित किये गये हैं। 1989 से 2004 तक, आम चुनावों में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। इनमें से कुछ गठबंधन खास तौर पर अराजक रहे हैं: 1989 और 1999 के बीच, आठ गठबंधन बने और कई जल्दी ही टूट गए (रूपारेलिया 2015, पृष्ठ संख्या-22) । 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार भारत में गठबंधन सरकार 2024 में 18वीं लोकसभा में बनी, जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम से एक बार फिर से भारत की राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। दरअसल 16वीं लोकसभा (2014) और 17वीं लोकसभा (2019) में भी एनडीए गठबंधन की ही सरकार थी लेकिन इन दोनों लोकसभा में भाजपा को अकेले ही बहुमत हासिल हुआ था। 18वीं लोकसभा में (2024) एनडीए गठबंधन की सरकार बनी लेकिन भाजपा को अकेले बहुमत हासिल नहीं हुआ। वर्तमान केंद्र सरकार जनता दल (यूनाइटेड), तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी), शिवसेना (शिंदे) जैसी क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। इस साल का सबसे बड़ा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, भाजपा के लिए एक गतिरोध साबित हुआ, क्योंकि

वह अकेले दम पर बह्मत हासिल करने में नाकाम रही। भाजपा ने 240 सीटें जीतीं, जो बहुमत के लिए ज़रूरी 272 सीटों से कम थीं। इस बीच, इन चुनावों में क्षेत्रीय दलों का उदय भी देखने को मिला, जो निर्णायक भूमिका में उभरे। क्षेत्रीय दलों ने इस साल भाजपा और कांग्रेस से सीटें हासिल करके महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की । एन चंद्रबाबू नायडू की तेल्गु देशम पार्टी (टीडीपी) ने 2024 में उल्लेखनीय वापसी की । इसने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में अभूतपूर्व चुनावी जीत दर्ज की और साथ ही, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडी(यू) इस साल एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली पार्टी बनकर उभरी। तेलुगु देशम पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के विपरीत, जेडी(यू) के नतीजे कई राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्यजनक रहे। बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) ने भाजपा की सीटों के बराबर, 40 में से 12 सीटें जीतीं। चूँिक भाजपा केंद्र में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही, इसलिए नीतीश कुमार सरकार गठन में किंगमेकर की भूमिका में आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी (सपा) ने लोकसभा चुनावों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की । प्रमुख राजनीतिक दलों में, सपा ने सबसे अधिक सफलता दर हासिल की और 62 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटों पर विजयी हुई । इसके विपरीत, भाजपा 76 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 33 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई । भाजपा और कांग्रेस के अलावा, सपा लोकसभा में तीसरी सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी भी बन गई। तृणमूल कांग्रेस भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत दावेदारों में से एक साबित हुई, यही वजह है कि वर्ष 2024 के अंत तक ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की नेता बनने का दावा पेश कर दिया (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-95)।

लोकसभा चुनाव में, तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीतीं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की आठ जीती हुई सीटें हासिल की । वर्ष 2024 में जम्मू-कश्मीर में आखिरकार एक दशक बाद एक सरकार के लिए मतदान हुआ और स्पष्ट विजेता उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) रही। लोकसभा चुनावों में, पार्टी ने कुल पाँच में से दो सीटें जीतीं। भाजपा को भी दो सीटें मिली, जबिक एक कांग्रेस के खाते में गई। सबसे चौंकाने वाला विधानसभा चुनाव था जिसमें एनसी ने 90 में से 42 सीटें हासिल कीं और यह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एमके स्टालिन के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) ने तमिलनाड् लोकसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की, पुड्चेरी की एकमात्र सीट सहित सभी 40 सीटों पर जीत हासिल की और दोनों प्रमुख विपक्षी दलों, अन्नाद्रमुक और भाजपा को करारी शिकस्त दी। द्रमुक की यह जीत इसलिए हुई क्योंकि पार्टी ने अपने तीन साल के शासन में लागू कल्याणकारी कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-98)। यह परिणाम अन्नाद्रमुक के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने 2016 में जे जयललिता के निधन के बाद से कोई चुनाव नहीं जीता था। महाराष्ट्र में विभाजित हुए दो दलों के दो गुट इस वर्ष हमेशा की तरह प्रासंगिक रहे। इस वर्ष दोनों खेमों के बीच उतार-चढ़ाव भरा खेल देखने को मिला । लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र विकास अगाड़ी (एमवीए) ने राज्य की 48 संसदीय सीटों में से 30 पर जीत हासिल की। 18वीं लोकसभा चुनाव में उद्धव की शिवसेना ने 9 बनाम शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीतीं। एनसीपी बनाम एनसीपी में, शरद पवार को 8 सीटें मिलीं और अजित पवार के गुट को केवल एक सीट

झारखंड में एक उल्लेखनीय चुनावी नतीजे के साथ, इस साल सत्तारूढ़ सरकार को दोबारा न चुनने का 24 साल पुराना सिलसिला टूट गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने दो-तिहाई बहुमत हासिल करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। इस वर्ष 2024 की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद निराशा में डूबे हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए एक शानदार बदलाव किया। सोरेन

की जेएमएम ने राज्य की कुल 81 सीटों में से 34 सीटें जीतीं, जबिक भाजपा 21 सीटें ही हासिल कर पाई । इसके अलावा कई क्षेत्रीय दल जिसका कभी राष्ट्रीय राजनीति में दबदबा था उदाहरण के लिए के॰ चंद्रशेखर राव की बीआरएस और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (बीजद) न केवल चुनाव हार गईं, बिल्क राज्य से भी बाहर हो गईं । पिछले साल रेवंत रेड्डी से सत्ता गंवाने के बाद, केसीआर की पार्टी इस साल लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही । तेलंगाना में भाजपा और कांग्रेस ने 8-8 सीटें जीतीं, जबिक एआईएमआईएम ने 1 सीट जीती । बीजद ने 1997 से ओडिशा पर शासन किया था, लेकिन इस बार भाजपा से हार गईं और मुख्यमंत्री के रूप में नवीन पटनायक का 24 साल पुराना शासन टूट गया । भाजपा ने 147 सीटों वाली विधानसभा में 78 सीटें हासिल कीं । बीजद ने बहुमत के निशान 74 से 51 सीटें पीछे और कांग्रेस ने 14 सीटें हासिल कीं । क्षेत्रीय दलों के लिए 2024 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा क्योंकि इस वर्ष राष्ट्रीय मंच पर उनकी बड़े पैमाने पर वापसी होगी।

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उभार

लोकतंत्र में, राजनीतिक दल समाज को विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचार एकत्र करने और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक एजेंसी प्रदान करते हैं। वे विभिन्न प्रतिनिधियों को एक साथ लाते हैं तािक एक उत्तरदायी सरकार का गठन हो सके। वे सरकार का समर्थन या नियंत्रण करने, नीितयाँ बनाने, उन्हें उचित ठहराने या उनका विरोध करने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। चुनाव आयोग चुनावों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, भारत में 2000 से अधिक एजनीतिक दल हैं, जिनमें छह "मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय" और 50 से अधिक "मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय" दल शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियाँ, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी के अलावा, देश के अधिकांश प्रमुख दलों को चुनाव आयोग द्वारा 'राज्यीय दल' के रूप में वर्गीकृत किया गया है (एल्लप्पा, संगीता 2020, पृष्ठ संख्या-28)। इन्हें आमतौर पर क्षेत्रीय दल कहा जाता है।

भारतीय दलीय व्यवस्था में उल्लेखनीय विकास हुआ है, खासकर पिछले चार दशकों में क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ । इन दलों ने राजनीतिक परिदृश्य में विविधता ला दी है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है और राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है। हालाँकि, गुटबाजी, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव और जवाबदेही जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजुद हैं। अधिक समावेशी और प्रभावी राजनीतिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इन गतिशीलता को समझना अत्यंत आवश्यक है। पिछले चार दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में विस्तार हुआ है, जिससे भारतीय संसद में अधिक विविधतापूर्ण राजनीतिक परिदृश्य सामने आया है । क्षेत्रीय दल अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उभरे हैं, जो विभिन्न राज्यों और समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय दलों को लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण स्थिर सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना आवश्यक हो गया है। 1977 से क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर शासन और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया है (के.के. 2014, पृष्ठ संख्या-85)।

क्षेत्रीय दलों के मुद्दों और आकांक्षाओं के प्रति केंद्र की संवेदनशीलता भारत की दलीय प्रणाली के संघीय चिरत्र को उजागर करती है, तथा शासन में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के महत्व को दर्शाती है। क्षेत्रीय दल विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, असम गण परिषद और नागा पीपुल्स फ्रंट। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने क्षेत्रीय असंतुलन और आर्थिक असमानताओं के कारण झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। विकास नीतियों के कार्यान्वयन

में विफलता के बाद पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी का उदय । शिवसेना पार्टी की स्थापना क्षेत्रीय नेताओं के करिश्माई व्यक्तित्व का उदाहरण है जिसकी स्थापना महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे ने की थी। राजद. जदयू, समाजवादी पार्टी आदि जैसे दलों का उदय बड़े दलों के भीतर विभिन्न गुटों में विभाजित होने का परिणाम है। भारतीय समाज में अनेक जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और जातिगत सम्हों की उपस्थिति क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति और विकास के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है (राथर 2020, पृष्ठ संख्या-9)। भारत में क्षेत्रीय दल पहचान, राज्य का दर्जा, स्वायत्तता और विकास आदि जैसे विषयों पर आधारित होते हैं। स्वायत्तता में राज्यों से अधिक शक्तियां मांगने की बात शामिल है (जैसे जम्म् और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस)। राज्य का दर्जा देश के भीतर एक स्वतंत्र राज्य के लिए संघर्ष करने से संबंधित है (जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग की थी) । पहचान में किसी समृह के सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता के लिए संघर्ष करना शामिल है (जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना या दलितों की पहचान के लिए संघर्ष करने वाली डीएमके)। विकास में क्षेत्रीय दलों का यह विश्वास शामिल है कि केवल वे ही किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए विकास ला सकते हैं। कभी-कभी क्षेत्रीय दल चुनावी लाभ के लिए ये 'सांस्कृतिक विशिष्टताएं' पैदा करते हैं। पिछले चार दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारत की संसद राजनीतिक रूप से अधिक विविध हो गई है । क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभरे हैं। कोई भी राष्ट्रीय दल लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाता । नतीजतन, राष्ट्रीय दलों को राज्य स्तरीय दलों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 1989 से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बदौलत ही हमारी दलीय व्यवस्था संघीय हो पाई है। केंद्र ने उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनकी आकांक्षाओं को परा करने के लिए समायोजन करना शुरू कर दिया है। हमारी दलीय प्रणाली की विकासशील प्रकृति ने हमारी संघीय प्रणाली की सहकारी प्रवृत्तियों को मजबूत किया है (अनुराग 2022, पृष्ठ संख्या-6)।

भारत में क्षेत्रीय दलों का उभार कई चरणों में हुआ । भारत में 1952-64 तक राष्ट्रीय सहमति का नेहरु युग था। इस दौर में कांग्रेस पार्टी प्रमुख पार्टी थी और भारतीय लोकतंत्र मुलतः एकदलीय प्रणाली थी जिसे 'कांग्रेस प्रणाली' भी कहा जाता था। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के रूप में विकसित हुई जो एक बड़ी छतरी की तरह थी जिसके नीचे सभी समुदायों, हितों और विचारधाराओं को जगह मिली। कांग्रेस के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली कई छोटी पार्टियाँ थीं, लेकिन वे मुख्य रूप से एक प्रकार के दबाव समृह के रूप में काम करती थीं। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में 1964-1977 का दौर संक्रमण राजनीति का दौर था। जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु के साथ ही 1967 के चुनावों ने कांग्रेस प्रणाली के प्रभुत्व को चुनौती दे दी। कांग्रेस आठ राज्यों में बहुमत हासिल करने में विफल रही और लोकसभा में उसका बहुमत बहुत कम 54 प्रतिशत सीटों तक सिमट गया (येरंकर 2015, पृष्ठ संख्या-404) । पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियाँ बढ़ने लगीं । कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष की एक श्रृंखला शुरू हो गई। अंततः 1969 में पार्टी का विभाजन हो गया और पार्टी तथा सरकार दोनों में इंदिरा गांधी का वर्चस्व स्थापित हो गया। हालाँकि, गुजरात में मोरारजी देसाई और बिहार में जेपी (जयप्रकाश नारायण) जैसे कुछ नेताओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और मनमाने शासन के खिलाफ सफल आंदोलन चलाया । उनका आंदोलन 1975 में चरम पर पहुंच गया जब इंदिरा गांधी ने भारतीय इतिहास में पहली और एकमात्र बार आंतरिक आपातकाल लगाने का फैसला किया। एक नई सहमति और बढ़ते अंतर-पार्टी संघर्ष का दौर 1977-80 का था (तुम्माला 2009, पृष्ठ संख्या-332) । 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में नया गठबंधन उभरा। इसके परिणामस्वरूप भारत में बहुदलीय प्रणाली का उदय हुआ । कई छोटी पार्टियां किसी वैचारिक सहमित के बजाय कांग्रेस के प्रभुत्व से लड़ने के लिए एक साथ आई थीं। लेकिन, वैचारिक रूप से सुसंगत नीति के अभाव के कारण जनता पार्टी का पतन हो गया और 1980 में कांग्रेस सत्ता में आ गयी। केंद्र में कांग्रेस और

राज्य स्तर पर नव उभरे क्षेत्रीय दलों के बीच संघर्ष का दौर 1980-90 का था। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपित शासन का अनुचित उपयोग किया गया। हालाँकि, क्षेत्रीय दल मजबूत हुए और उन्होंने केंद्र की राजनीति में अधिक मुखर भूमिका निभानी शुरू कर दी। आठवें लोकसभा चुनाव (1984) में आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। बहुदलीय प्रणाली और गठबंधन राजनीति राजीव गांधी की मृत्यु, भ्रष्टाचार के मामले (बोफोर्स घोटाला), आर्थिक संकट, इन सभी ने गठबंधन के युग की नींव रखी जो लगभग पच्चीस वर्षों तक गठबंधन सरकारों के रूप में चला।

1989-2014 का दौर बहुदलीय प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप गठबंधन राजनीति का आध्निक युग अस्तित्व में आया है। हालाँकि, यह अवधि गठबंधन की मजब्रियों से प्रभावित है। क्षेत्रीय दलों के विकास से 'इंद्रधन्ष' गठबंधन भी बनते हैं, जिन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंद्रधनुष की तरह ये भी थोड़े समय तक ही टिकते हैं। 1996-1999 की अवधि में तीन आम चुनाव हुए, जिनमें जनता का बहुत पैसा खर्च हुआ । नीतिगत पक्षाघात और निर्णय लेने तथा विधेयक बनाने में देरी, ये सभी गठबंधनों के कारण होते हैं। आपातकालीन समय में. गठबंधन समन्वय से अस्वीकार्य विलंब हो सकता है। गठबंधन सरकार निर्णय लेने की प्रक्रिया और निर्णय कार्यान्वयन के संचालन में बाधा डाल सकती है। गठबंधन सरकार ने उत्तर भारत की राजनीति को जाति और समुदाय आदि के आधार पर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा में बदल दिया है। इसके विपरीत, गठबंधन के समय में, क्षेत्रीय दलों ने बहिष्कारवादी राष्ट्रीय दलों पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति के रूप में कार्य किया। क्षेत्रीय दल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए खाली स्थान को भरते हैं। गठबंधन की राजनीति ने राज्यों के क्षेत्रीय दलों को सशक्त बनाया है और भारत की सच्ची संघवाद की खोज को बल दिया है (रूपारेलिया 2015, पृष्ठ संख्या-54)। इस प्रकार, यह एक प्रकार के 'चुनावी संघवाद' का मार्ग प्रशस्त करता है। 1996 से 23 क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता साझा कर रहे हैं। यहां भारतीयता की भावना प्रबल है, जिसे संघीय एकीकरण कहा जाता है। 2014 से 2024 तक एकदलीय प्रणाली का पुनरुत्थान का दौर था। दो आम चुनावों 2014 और 2019 में एक ही पार्टी (भाजपा) को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला, जिससे गठबंधन की राजनीति की 25 साल की मजबूरियां टूट गई। हालाँकि सरकार अभी भी कई राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय दलों का दृष्टिकोण अब केन्द्र-राज्य संबंधों के संबंध में संघर्षपूर्ण रुख से बदलकर सहयोगात्मक सौदेबाजी की प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। अब केन्द्र-राज्य संबंधों में वित्तीय समस्याएं मुख्य ध्यान का केन्द्र हैं। आज क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को एक नया आयाम प्रदान किया है।

हाल के दशकों में दक्षिण भारत का राजनीतिक परिवेश नाटकीय रूप से बदला है, जिसमें क्षेत्रीय दलों का विकास और एकीकरण प्रमुख भूमिका में है। ये दल प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए उभरे हैं, राष्ट्रीय दलों के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं और अपने स्थानीय राज्यों के विशिष्ट हितों के लिए ज़ोरदार पैरवी कर रहे हैं। इस निबंध में, हम दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों की स्थापना में योगदान देने वाले मूलभूत तत्वों और क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता पर उनके गहरे प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्रवाद का इतिहास स्वतंत्रता के बाद के युग से जुड़ा है। हालाँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को व्यापक समर्थन प्राप्त था, लेकिन उन्हें क्षेत्र के विभिन्न लक्ष्यों को पुरा करने में संघर्ष करना पड़ा । परिणामस्वरूप, करिश्माई क्षेत्रीय नेता उभरे, जो अपने मतदाताओं से गहराई से जुड़े थे और अपने राज्यों के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ थे । इन राजनेताओं ने शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के उदय की नींव रखी। दक्षिण भारत की भाषाई विविधता ने क्षेत्रीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया है, जहाँ तमिल, तेलुग्, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएँ कई राज्यों में बोली जाती हैं। क्षेत्रीय दल अपने समर्थकों में पहचान और गौरव की गहरी भावना पैदा करने के लिए भाषाई विविधता का उपयोग करते हैं (पाई 1990, पृष्ठ संख्या-395) । ये दल स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को बढ़ावा देकर जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हैं और उनमें एकता और अपनेपन की सच्ची भावना का निर्माण करते हैं। भारत में, विकेंद्रीकरण आंदोलन ने क्षेत्रीय दलों को स्थानीय शासन और निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव डालने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। राज्यों को सत्ता के और अधिक हस्तांतरण से, ये दल अपने मतदाताओं की चिंताओं का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकप्रिय समर्थन और चुनावी सफलता में वृद्धि होगी।

दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों के पुनरुत्थान ने क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये दल अपने-अपने राज्यों के उत्साही समर्थक के रूप में विकसित हुए हैं और अपने मतदाताओं के विविध लक्ष्यों और चिंताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते रहे हैं। क्षेत्रीय दलों ने भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विशिष्टता को अटट रूप से बढ़ावा देकर राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट जगह बनाई है। दक्षिण भारत के भविष्य को आकार देने में क्षेत्रीय दलों का महत्व निश्चित रूप से और भी अधिक महत्वपूर्ण होता जाएगा क्योंकि वे अपनी शक्ति को निरंतर मजबूत और बढ़ाते जा रहे हैं। क्षेत्रीय दलों ने भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की प्रकृति पर गहरा प्रभाव डाला है। वे भारत जैसे बह-जातीय, बह-नस्लीय, बह-धार्मिक और बहुभाषी समाज में वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम हैं। इस प्रकार, उनका विकास लोकतंत्र की संपूर्ण भावना के साथ तालमेल बिठाता है। क्षेत्रीय दलों ने प्रांतों के लिए अधिक स्वायत्तता की वकालत करते हए केंद्र-राज्य संबंधों की प्रकृति और दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने क्षेत्रीय सरकारों में बेहतर शासन और स्थिरता में योगदान दिया है। क्षेत्रीय दलों ने चनावों के दौरान मतदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार किया है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी है (येरंकर 2015, पृष्ठ संख्या-403) । उन्होंने जनता के बीच राजनीतिक चेतना को बढ़ाया है, तथा क्षेत्रीय मुद्दों और चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। क्षेत्रीय दलों ने भारत में एकदलीय प्रभुत्व को चुनौती दी है, जिसके कारण विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रभाव में गिरावट आई है। क्षेत्रीय दलों के उदय ने राजनीति को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय दलों ने प्रमुख राष्ट्रीय दलों को संघर्ष समाधान के लिए अधिक उचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी में राज्यपालों की पक्षपातपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में, विशेषकर गठबंधन शासन के संदर्भ में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने केंद्र में गठित गठबंधन सरकारों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और राष्ट्रीय दलों के साथ सत्ता साझा की है।

भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत

1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तब से लेकर अब तक भारत के 73 साल के चुनावी इतिहास में, देश में 32 साल गठबंधन सरकारें रही हैं। इसके विपरीत, 31 साल बहुसंख्यकवादी सरकारें रही हैं, जिनमें से 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहे हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति 20वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रमुखता से उभरने लगी । इससे पहले, भारतीय राजनीति पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) का प्रभुत्व था, जिसका आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में राजनीतिक सत्ता पर लगभग एकाधिकार था । हालाँकि, राजनीतिक परिदृश्य, विशेष रूप से 1970 के दशक के बाद से, विखंडित होने लगा, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और एकल-दलीय प्रभुत्व का हास हुआ । तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल (1975-1977) के दौरान व्यापक असंतोष फैला। 1977 के चुनावों में, जनता पार्टी सहित विपक्षी दलों का एक गठबंधन सत्ता में आया, जो भारत की पहली महत्वपूर्ण गठबंधन सरकार थी। भारत की पहली गठबंधन सरकार 1977 में कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद बनी थी। 1947 में अंग्रेजों से देश की आज़ादी के बाद से यह पार्टी की पहली हार थी। 1977 के चुनाव कांग्रेस नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के लगभग दो साल बाद हुए थे। गांधी ने आपातकाल हटा लिया और जनवरी 1977 में शीघ्र चुनावों की घोषणा की । इंदिरा गांधी को जनता पार्टी नामक विविध दलों के गठबंधन से हार का

सामना करना पड़ा, जिसमें भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ भी शामिल थी (मैकिमलन 2014, पृष्ठ संख्या-8)। इस गठबंधन के अन्य दलों में भारतीय लोक दल (बीएलडी) शामिल था-जो सात क्षेत्रीय वामपंथी दलों, समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बना एक गठबंधन था। उन चुनावों में जनता पार्टी की जीत के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। हालाँकि, आंतरिक कलह के कारण यह सरकार तीन साल के भीतर ही गिर गई।

स्वतंत्र भारत में पहली बार 1977 में आपातकाल के ठीक बाद, विभिन्न दलों ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी। भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ सहित ग्यारह दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनाई। यह इंद्रधनुषी गठबंधन 1979 तक चला। किसान नेता चरण सिंह इंदिरा गांधी की कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। हालाँकि, इंदिरा ने 23 दिन बाद ही चरण सिंह को सत्ता से बेदखल कर दिया। गठबंधन सरकार चलाने में यही जोखिम है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन दो साल तक चला, जब तक कि वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी टूट नहीं गई। देसाई के गृह मंत्री चरण सिंह को मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया, जिसके बाद वे अलग हो गए। 1979 में जनता पार्टी के अलग-अलग गुटों और कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन चरण सिंह का प्रधानमंत्रीत्व केवल 23 दिनों तक चला क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी सत्ता में लौटीं, कांग्रेस ने 353 सीटें जीतीं। जनता पार्टी (सेक्युलर), जो जनता पार्टी का एक गृट था, ने 41 सीटें जीतीं और उस समय दसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में लौटीं और 1984 में अपनी हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति वोटों के सहारे कांग्रेस 1984 में अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। कांग्रेस पार्टी ने 541 लोकसभा सीटों में से 414 सीटें जीतीं। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जो ऐतिहासिक जनादेश मिला, वह कांग्रेस के लिए शिखर था (श्रीधरन 2004, पृष्ठ संख्या-5422)। उसके बाद से पार्टी की सीटें लगातार घटती गईं। यह आखिरी बार था जब देश को लंबे समय तक एकदलीय शासन देखने को मिला।

1989 के चुनाव परिणाम भारत के लिए एक नया ऐतिहासिक क्षण लेकर आए: यह पहली बार था जब इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 529 में से 197 सीटें जीती थीं, जिसके बाद किसी भी पार्टी या चुनाव-पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था (येरंकर 2015, पृष्ठ संख्या-403)। 1989 से 1991 तक, देश ने दो गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को देखा-वीपी सिंह और चंद्रशेखर । 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव ने 5 साल के लिए पहली कांग्रेस गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। गठबंधन की राजनीति का युग जारी रहा और 1996 से 1998 तक, हमारे पास तीन प्रधानमंत्री थे। जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत छोटा 15 दिन का कार्यकाल शामिल था। इस अवधि में गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले अन्य दो क्षेत्रीय नेता एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल थे। गठबंधन की मजबूरियों ने सुनिश्चित किया कि दो साल में दो बार लोकसभा चुनाव हुए 1999 में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने चुनाव पूर्व गठबंधन के रूप में बहुमत हासिल किया। वाजपेयी पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पूर्व कांग्रेस नेता और वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी पूर्व पार्टी, जिसे उन्होंने 1987 में छोड़ दिया था, के विरुद्ध राष्ट्रीय मोर्चा नामक एक नया गठबंधन बनाया। वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चे ने 143 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने 85 सीटें जीतीं-1980 में पार्टी के गठन के बाद से यह उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वी.पी. सिंह 1989 में भाजपा के समर्थन से प्रधानमंत्री बने (खान 2003, पृष्ठ संख्या-169)। वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा ने भाजपा और वाम मोर्चे के बाहरी समर्थन से 1989-1991 में सरकार बनाई। इसी दौर में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, जिससे सामाजिक उथल-पुथल मची और अंततः सरकार गिर गई । 1990 में उनकी सरकार गिर गई जब भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जब उसके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए उनकी देशव्यापी यात्रा के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उस समय 16वीं सदी की एक मस्जिद थी। जनता दल (जेडी) के विरष्ठ नेता चंद्रशेखर ने 1990 में पार्टी-जो राष्ट्रीय मोर्चा का हिस्सा थी-को तोड़कर समाजवादी जनता पार्टी का गठन किया। नवंबर 1990 में कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से वे वी.पी. सिंह के बाद प्रधानमंत्री बने। कुछ ही महीनों बाद उनकी सरकार भी गिर गई, जिससे अल्पकालिक गठबंधन सरकारों का सिलसिला खत्म हो गया। 1991 के चुनावों में, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसका मुख्य कारण राजीव गांधी की एक चुनावी रैली के दौरान हुई हत्या पर उपजे सहानुभूति का प्रभाव था (चंदर 2004, पृष्ठ संख्या-29)। कांग्रेस नेता पी.वी. नरसिम्हा राव जनता दल के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने। राव सरकार ने, जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया, आर्थिक सुधारों की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों में उच्च विकास दर का मार्ग प्रशस्त किया।

भाजपा 1996 में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। पार्टी ने 161 सीटें जीतीं, जबिक कांग्रेस 140 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, और जनता दल 46 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही (फ़ारूक़ी और श्रीधरन 2014, पृष्ठ संख्या-562)। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन संसद में बहमत हासिल नहीं कर सके। उनकी सरकार केवल 13 दिनों तक चली। उनके बाद एचडी देवेगौड़ा सत्ता में आए, जो संयुक्त मोर्चा के नेता थे-एक नया गठबंधन जिसमें जनता दल और तेलुग् देशम पार्टी (टीडीपी) के साथ-साथ वामपंथी और कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी शामिल थीं। गठबंधन की कलह के कारण देवेगौड़ा की सरकार एक साल के भीतर ही गिर गई। उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल ने सत्ता संभाली, लेकिन उनकी सरकार भी एक साल से ज़्यादा नहीं चल सकी। 1996 के चुनावों के बाद, किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा (कई क्षेत्रीय दलों का गठबंधन) के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनी। इस दौर में प्रधानमंत्रियों एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल के नेतृत्व में दो अल्पकालिक सरकारें बनीं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेतृत्व करते हुए गठबंधन राजनीति में एक महत्वपुर्ण भुमिका में उभरी।

भाजपा नेता वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने 1999 में 182 सीटें जीतकर विजय हासिल की। सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बनाई, जो 2004 तक चली। एनडीए का कार्यकाल आर्थिक सुधारों और भारत की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए जाना जाता है।

तालिका 1: गठबंधन राजनीति के प्रमुख चरण

राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख गठबंधन	कार्यकाल
जनता पार्टी प्रयोग	1977-1980
राष्ट्रीय मोर्चा सरकार	1989-1991
संयुक्त मोर्चा सरकारें	1996-1998
एनडीए का उदय	1998-2004
यूपीए युग	2004-2014
एनडीए की वापसी	2014-2029

स्रोत: एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म

सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की आश्चर्यजनक वापसी हुई, जो 2014 तक दो कार्यकालों तक सरकार में रहा। इसने एक नया गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) बनाया। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में भारत के आर्थिक सुधारों के सूत्रधार मनमोहन सिंह को नया प्रधानमंत्री चुना गया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन 2009 के चुनाव में प्रभावशाली आर्थिक विकास के दम पर दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुआ। एक बार फिर, कांग्रेस ने 2009 से 2014 तक एक गठबंधन के मुखिया के रूप में शासन किया-उसके पास अकेले बहुमत नहीं था। यूपीए-1 और यूपीए-2 दोनों में - 2004 से 2014 तक - कांग्रेस ने गठबंधन सरकारें चलाईं। 25 वर्षों के लंबे

अंतराल के बाद, 2014 में ही किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। एनडीए सहयोगियों के चुनाव-पूर्व गठबंधन का नेतृत्व करने वाली भाजपा ने 2014 में नरेंद्र मोदी लहर पर सवार होकर 282 सीटें जीती थीं और 272 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया था। पाँच साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद, भाजपा 2019 में 303 सीटें जीतकर अपने दम पर सत्ता में लौटी। पुलवामा हमला, जिसमें आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के 40 जवानों को मार डाला था, 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बन गया। हालांकि, 1989 में, क्षेत्रीय दलों को प्रमुखता मिली क्योंकि कांग्रेस ने जमीन खोनी शुरू कर दी। भव्य-पुरानी पार्टी पांच साल पहले जीती गई सीटों में से आधे से भी कम सीटें बरकरार रख सकी। कांग्रेस के पतन ने भारतीय राजनीति में एक और गठबंधन युग की शुरुआत की (चंदर 2004, पृष्ठ संख्या-12)।

2014 में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 282 सीटें जीतीं, जो लोकसभा में आधे के निशान से 12 अधिक थीं। 1984 के बाद यह पहली बार था जब किसी पार्टी ने अपने दम पर बह्मत हासिल किया था। भाजपा को शो चलाने के लिए किसी क्षेत्रीय सहयोगी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें पहली एनडीए सरकार का हिस्सा बनाया। पांच साल बाद 2019 में, भाजपा ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और इस बार अपने दम पर 303 सीटें जीतीं। एनडीए 2.0 में भाजपा के सहयोगियों के लिए भी जगह थी। 2024 में, भाजपा "400 पार" के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। पार्टी और उसके सहयोगी दलों को एक और शानदार चुनावी प्रदर्शन और भगवा पार्टी की लगातार तीसरी क्लीन स्वीप का भरोसा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस साल 4 जून को जब नतीजे घोषित हुए, तो भाजपा बहुमत के आंकड़े से चूक गई । और इसने एनडीए के क्षेत्रीय सहयोगियों को फिर से प्रमुखता में ला दिया। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए 3.0 को आगे बढ़ाने वाले किंगमेकर बनकर उभरे और यह सुनिश्चित किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आएँ। इस साल के बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष पैकेज और घोषणाओं का बोलबाला रहा, ये राज्य एनडीए 3.0 के अस्तित्व में अहम भूमिका निभाते हैं (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-110)। 10 साल के पूर्ण प्रभुत्व के बाद, भाजपा ने बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के साथ अच्छी तरह तालमेल बिठा लिया है और कम से कम अभी के लिए, अपने सहयोगियों को खुश रखने में कामयाब रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के गठबंधन से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 2023 में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कई विपक्षी दलों द्वारा गठित इंडिया (भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास गठबंधन) गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उथल-पृथल का सामना करना पड़ा। हालाँकि, तमाम अंतर्विरोधों और चुनौतियों के बावजूद, यह भाजपा को लगातार तीसरी बार अकेले बहुमत हासिल करने से रोकने में कामयाब रहा। भारत के प्रमुख राज्यों में सहयोगियों की मदद से, कांग्रेस निचले सदन में अपनी संख्या लगभग दोग्नी करने में सफल रही, लेकिन फिर भी तीन अंकों के आंकड़े से एक सीट पीछे रह गई।

18वीं लोकसभा में गठबंधन राजनीति की वापसी

18वीं लोकसभा चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि केंद्र में एकदलीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक दशक के प्रभुत्व के बाद क्षेत्रीय राजनीतिक दल मुख्य राजनीतिक मंच पर वापस आ गए हैं। 18वीं लोकसभा लोकसभा में शक्ति संतुलन को लेकर पिछली दो लोकसभाओं से भिन्न है। इसने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का पुनरुत्थान देखा, जिसमें 14 क्षेत्रीय दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) गठबंधन को 292 सीटों का समर्थन दिया। दो क्षेत्रीय राजनीतिक हस्तियां, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल (यूनाइटेड) के नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री (पीएम) के रूप में शपथ लेने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। भाजपा ने 240 सीटें जीतीं, जो 272 के बहुमत से 32 सीटों से कम रही, जबिक 2019 के चुनाव में 303 सीटों के साथ इसकी जीत हुई थी (अनुराग 2022, पृष्ठ संख्या-5)। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के उदय और सभी क्षेत्रों में

व्यापक जनसमर्थन के साथ, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत कम गुंजाइश बची थी। पिछले दस वर्षों में, संसद में लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था, जिसे 18वीं लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक लोकसभा सीटें जीतने के बाद बदल दिया गया है। इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों को मिली महत्वपूर्ण बढ़त में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (सपा), आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बिहार में नीतीश की जेडी(यू), महाराष्ट्र में उद्भव ठाकरे की शिवसेना, महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) शामिल हैं। हालाँकि इनमें से ज्यादातर पार्टियाँ विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) के साथ हैं, लेकिन जनादेश ने उन्हें संसद में राज्य-विशिष्ट मुद्दों को ज़ोरदार तरीक़े से उठाने के लिए मज़बूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में चंद्रबाब् नायडू और नीतीश कुमार किंगमेकर की भूमिका में हैं। यह भारतीय संसदीय प्रणाली में गठबंधन राजनीति के पुनः प्रवेश का संकेत है। इस चुनाव से पहले, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका सीमित थी। इसके विपरीत, केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमुल कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों में राजनीतिक रूप से मज़बूत थे। 2024 का चुनाव भारत में विविधता को पुनर्जीवित करने का एक उदाहरण है। क्षेत्रीय दलों का फिर से उभरना इस बात का भी संकेत है कि मतदाता 2019 के चुनाव के विपरीत, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बजाय स्थानीय नेताओं और स्थानीय कारकों को प्राथमिकता दे रहे हैं (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-97)। यह संघवाद को मज़बूत करेगा क्योंकि स्थानीय हितों के रूप में केन्द्रापसारक शक्तियों को गठबंधन सरकार और विपक्ष में नया जोश मिलेगा।

18वीं लोकसभा चुनाव ने भारत की बहुआयामी बहुलता को पुनर्जीवित किया है क्योंकि क्षेत्रीय दलों का आकार बढ़ा है और संसद में उनकी उपस्थिति को बढ़ावा मिला है। यह विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करके एक वास्तविक आम सहमति बनाएगा। क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा पेश किए गए विधेयकों के पारित होने को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं, यह देखना बाकी है क्योंकि संसद में क्षेत्रीय दलों का आकार विपक्षी दलों में अधिक प्रमुख है। फिर भी, संसद में क्षेत्रीय आवाज़ें गूंजेंगी, जो जातीय, धार्मिक और भाषाई आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करेंगी। क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित राज्यों को उम्मीद है कि 16वां वित्त आयोग वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा, कठिन वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए करों के बंटवारे और अनुदानों की सिफ़ारिश करेगा, और वित्तीय स्थिरता स्थापित करेगा। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयकरण के पुनः उभरने के साथ, केंद्र सरकार को क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उससे विकास की अपेक्षाओं की याद आती दिख रही है। 18वीं लोकसभा भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करती है, और इससे उच्च उम्मीदों के साथ और अधिक क्षेत्रीय दल अपनी आवाज़ उठा सकते हैं (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-112)।

लोकसभा चुनाव के नतीजों में, भाजपा स्वतंत्र रूप से 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई और उसे सरकार बनाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जद (यू) जैसे गठबंधन सहयोगियों के समर्थन की आवश्यकता होगी। यह घटनाक्रम भाजपा-बहुमत वाली सरकार के लगातार दो कार्यकालों के बाद गठबंधन सरकार की ओर वापसी का संकेत देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो खंडित जनादेश मिला है, उसमें उसे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जिसके पास 16 सीटें हैं, और नीतीश कुमार की जद(यू), जिसके पास 12 सीटें हैं, जैसे गठबंधन सहयोगियों के समर्थन की आवश्यकता होगी (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-98)। 2024 को 10 साल के अंतराल के बाद केंद्र में गठबंधन की राजनीति की वापसी के लिए याद किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए 3.0 सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां तक कि विपक्षी मंच पर भी क्षेत्रीय दलों के गठबंधन का दबदबा था-जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, लेकिन इस सबसे पुरानी पार्टी का दबदबा नहीं था। भाजपा, जिसने 2014 में अपने दम पर बहुमत हासिल करके और फिर 2019 में अपने प्रदर्शन को बेहतर करके इतिहास रचा था, 2024 में

बहुमत का आंकड़ा छूने में विफल रही। इससे ध्यान फिर से क्षेत्रीय दलों पर आ गया, जो एनडीए 1.0 और एनडीए 2.0 का हिस्सा होने के बावजूद गठबंधन में बहुत कम प्रभाव रखते थे क्योंकि भाजपा अपनी सरकारों के अस्तित्व के लिए उनकी संख्या पर निर्भर नहीं थी (राथर 2020, पृष्ठ संख्या-7)। 2014 से पहले, भारत ने आखिरी बार 1984 में लोकसभा में एक दलीय बहुमत देखा था, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 400 से अधिक सीटें जीती थीं। पिछले एक दशक में एक सर्वशक्तिमान सीईओ की तरह केंद्र में अपने दम पर सरकार चलाने के बाद, अब सबकी निगाहें नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में अपना लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए तैयार हैं, एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और भाजपा 2014 और 2019 के विपरीत, बहुमत हासिल करने से चूक गई है।

तालिका 2: 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम

प्रमुख राजनीतिक दल	कुल प्राप्त सीट
भारतीय जनता पार्टी	240
कांग्रेस	99
समाजवादी पार्टी	37
तृणमूल कांग्रेस	29
डीएमके	22
टीडीपी	16
जनता दल (यूनाइटेड)	12
शिवसेना (उद्भव)	9
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)	8
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	5

स्रोत: भारतीय चुनाव आयोग

2024 के लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के साथ, भारत लगातार दो बार एकदलीय शासन के बाद गठबंधन युग में लौट आया है। सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है और आधे का आंकड़ा पार कर गया है, लेकिन 2019 की तुलना में उसके पास बहुत कम बहुमत है। इसका मतलब है कि मोदी प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए वापसी कर रहे हैं, लेकिन वह पहली बार गठबंधन सरकार के शीर्ष पर हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार में नई राजनीतिक मजब्रियां है। एनडीए सरकार में गठबंधन सहयोगियों की उपस्थिति अपनी राजनीतिक मजब्रियों के साथ आयी है। इससे पता चलता है कि केंद्र में एक दशक तक मजबूत एजेंडा-संचालित नीतियों के बाद, हम देने और लेने की राजनीति के युग में लौटने की संभावना रखते हैं, जिसमें मोदी को टीडीपी और जेडीयू जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों की माँगों से निपटना होगा। यह परिणामी नीतिगत समझौतों का संकेत दे सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के गठबंधन से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। भाजपा की अपने प्रमुख गठबंधन सहयोगियों, दक्षिण की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और पूर्व की जनता दल (यूनाइटेड) पर निर्भरता, सरकार के घरेलू राजनीतिक कार्यक्रम में बदलाव ला सकती है। ये दोनों क्षेत्रीय दल अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं का बखान करते हैं और इनके पास मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी; शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़ी मानी जाने वाली जातियों का एक वर्गीकरण) वोट बैंक हैं, जो भाजपा की बहुसंख्यक हिंदुत्ववादी राजनीति के विपरीत है। मोदी की प्रमुख पहलों में से एक-समान नागरिक संहिता, जो विवाह, तलाक और अन्य व्यक्तिगत मामलों से जुड़ी पारंपरिक मुस्लिम प्रथाओं पर लगाम लगाएगी-अब संभवतः स्थगित कर दी जाएगी, जबिक विवादास्पद अग्निपथ योजना, जो युवाओं को चार साल की ड्यूटी के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती होने की अनुमित देती है, का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। भाजपा के घोषणापत्र में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के तहत एक साथ राज्य और राष्ट्रीय चुनाव लागु करने का वादा भी रद्द होने की संभावना है, जिसे अधिकांश क्षेत्रीय दल संघीय व्यवस्था का उल्लंघन मानते हैं। राजनीतिक स्थिरता भी एक मुद्दा हो सकता है (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-109)।

फिलहाल, भाजपा ने यह सुनिश्चित किया है कि कैबिनेट के 30 मंत्री पदों में से केवल पांच ही गठबंधन दलों के सदस्यों के पास हों, शीर्ष चार मंत्री पद भाजपा के पास ही रहें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 72 सदस्यों में से 11 भाजपा के गठबंधन सहयोगियों से हैं। हालाँकि, कुछ गठबंधन सहयोगी पहले से ही नाराज़ हैं और मंत्रिपरिषद का विस्तार चाहते हैं। तेलगु देशम पार्टी और जनता दल (युनाइटेड) दोनों ही अस्थिर सहयोगी रहे हैं, दोनों पहले विपक्षी गठबंधन के सदस्य थे (टीडीपी मार्च 2024 में एनडीए में और जद (यू) जनवरी 2024 में फिर से शामिल हो गई)। इसके अलावा, चुनावों के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया गठबंधन) का हौसला बढ़ा है, जिसने 232 सीटें जीती हैं (आईएनसी ने अपनी सीटों की संख्या लगभग दोगुनी करके 52 से 99 कर ली है)। हालाँकि यदि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार की तुलना किया जाए तो पता चलता है कि उस समय भाजपा के पास लोकसभा में केवल 182 सीटें थीं और उसने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से अपना पाँच साल का कार्यकाल (1999-2004) सफलतापूर्वक पूरा किया । इसलिए एक सफल गठबंधन सरकार चलाने के लिए, वर्तमान भाजपा नेतृत्व को कमज़ोर न दिखते हए भी अधिक उदार होना होगा। वर्तमान लोकसभा में 28 सीटों की अपनी सामृहिक ताकत के साथ, जद (यू) और टीडीपी ने न केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रति अपनी निष्ठा की पृष्टि की है, बल्कि सरकार बनाने के गठबंधन के प्रयास में निर्णायक खिलाड़ी के रूप में भी उभरे हैं (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-98)। उनका प्रभाव न केवल उनकी चुनावी सफलता का प्रमाण है, बल्कि एक सूक्ष्म मतदाता भावना का भी प्रमाण है जो राष्ट्रीय नीतियों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन चाहता है। अपने विजय भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रमशः बिहार और आंध्र प्रदेश में एनडीए के प्रदर्शन में नीतीश कुमार और चन्द्रबाब् नायड् दोनों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया । यह स्वीकारोक्ति भारतीय राजनीति की विकसित होती गतिशीलता को दर्शाती है, जहाँ क्षेत्रीय आवाज़ें अब केवल प्रतिध्वनियाँ नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के कोरस के केंद्र में हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन क्षेत्रीय ताकतों का पुनरुत्थान एक परिपक्व मतदाता वर्ग का संकेत देता है जो स्थानीय शासन को महत्व देता है और साथ ही व्यापक राष्ट्रीय आख्यान के साथ भी जुड़ा रहता है। जद (यू) और टीडीपी की रणनीतिक स्थिति, उन्होंने क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित रखने और राष्ट्रीय शासन में अपनी भूमिका स्थापित करने के लिए इसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि भले ही विपक्ष अभी या भविष्य में सरकार बनाए, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव सर्वोपरि रहेगा। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, स्थिर और समावेशी जनादेश प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाली किसी भी सरकार के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का एकीकरण आवश्यक

चूँकि क्षेत्रीय दल अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ अपने प्रभाव का दावा करते हुए और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को कायम रखते हुए निर्णायक भूमिका में उभरे हैं, अंतिम परिणाम ने भारतीय राजनीति में एक परिवर्तनकारी बदलाव को रेखांकित किया (शिंदे 2017, पृष्ठ संख्या-484)। यहाँ स्थानीय सरोकार केंद्र में आ गए, राष्ट्रीय आख्यानों के प्रभुत्व को चुनौती दी। अपने-अपने राज्यों में गहरी जड़ें जमाए इन दलों ने अपने मतदाताओं को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जोरदार प्रचार किया। दक्षिण में जल अधिकारों से लेकर पश्चिम में कृषि नीतियों तक, और पूर्व में रोजगार सूजन से लेकर उत्तर में बुनियादी ढाँचे के विकास तक, क्षेत्रीय दलों ने अपने घोषणापत्रों को अपने मतदाताओं की आकांक्षाओं और शिकायतों को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार किया। उनकी सफलता का श्रेय क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक बारीकियों के साथ प्रतिध्वनित होने की उनकी क्षमता को दिया जा सकता है, जो अक्सर राष्ट्रीय दलों की समझ से परे होती हैं। क्षेत्रीय स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित करके और अधिक विकेंद्रीकरण की वकालत करके, वे एक महत्वपुरण जनादेश हासिल करने में सफल रहे, जो लोकसभा में उनकी पर्याप्त उपस्थिति में परिवर्तित हो गया। चुनाव परिणामों ने एक ऐसी राजनीति को उजागर किया जो संघवाद के प्रति अधिक समर्पित थी, जहाँ मतदाताओं ने उन दलों का

समर्थन किया जिन्होंने व्यापक, एक-सा समाधान की बजाय क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देने का वादा किया था । यह परिणाम भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण है, जहाँ शासन में विविधता को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि उसका जश्न भी मनाया जाता है। 2014 के बाद से, भारत में लोकसभा चुनावों में अक्सर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे छाए रहे हैं। हालाँकि, 2024 के लोकसभा चुनाव इस प्रवृत्ति से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं, जहाँ क्षेत्रीय राजनीतिक दल प्रभावी रूप से क्षेत्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं और उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने अपने अभियान का ध्यान केवल केंद्र सरकार की आलोचना करने के बजाय, बेरोजगारी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खराब शासन पर केंद्रित किया। यह क्षेत्रीय फोकस मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिससे स्थानीय चिंताओं के साथ पार्टी का जुड़ाव प्रदर्शित हुआ। आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने अपने अभियान का ध्यान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर केंद्रित किया। मतदाताओं की विशिष्ट शिकायतों का समाधान करके, नायडू ने स्वच्छ शासन और क्षेत्रीय जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डाला । इसी तरह, पश्चिम बंगाल में, तृणम्ल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा बंगाल की उपेक्षा पर एक शक्तिशाली आख्यान का नेतत्व किया। ममता बनर्जी के अभियान ने क्षेत्रीय असमानताओं और अधिक राज्य स्वायत्तता की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसने मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाया। ये उदाहरण बताते हैं कि कैसे क्षेत्रीय दलों ने 2024 के चुनाव को क्षेत्रीय मुद्दों के मंच में सफलतापूर्वक बदल दिया (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-109)। ऐसा करके, उन्होंने न केवल क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को बरकरार रखा, बल्कि चुनावी परिदृश्य को भी पुनर्परिभाषित किया, भारत के लोकतंत्र में स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। यह बदलाव एक परिपक्व राजनीतिक माहौल का संकेत देता है जहाँ क्षेत्रीय आवाज़ें राष्ट्रीय विमर्श का अभिन्न अंग हैं।

गठबंधन की राजनीति का नया युग शुरू होना भारतीय राजनीति में एक बदलाव का संकेत देते हैं, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है जहाँ क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकारें तेजी से प्रमुख होती जा रही हैं। इस प्रकार यह राष्ट्रीय दलों के घटते प्रभुत्व और देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में क्षेत्रीय संस्थाओं के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बहमत में कमी आई है और उसे 291 सीटें मिली हैं, जबिक भारत-नेपाल गठबंधन ने 234 सीटों के साथ महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। भाजपा की अकेले बढ़त बहुमत के 272 के आंकड़े से कम है, जो सरकार बनाने के लिए गठबंधन सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाता है। भारतीय राजनीति में पारंपरिक रूप से एक केंद्रीय स्तंभ रही कांग्रेस पार्टी ने वापसी करते हुए 2019 की तुलना में अपनी सीटों की संख्या दोगुनी कर दी है और 93 सीटों पर बढ़त बना ली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय ताकतें अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, और पश्चिम बंगाल ने तो भाजपा पर बढ़त भी बना ली है। इसलिए ये नतीजे गठबंधन समीकरण में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करते हैं (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-110)। यह चुनाव दर्शाता है कि मतदाता राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व के दायरे से आगे बढ़कर अधिक स्थानीय और मुद्दा-आधारित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, खासकर हरियाणा, राजस्थान और केरल जैसे राज्यों में, पारंपरिक दलीय सीमाओं से परे मतदाताओं की सूक्ष्म प्राथमिकताओं का उदाहरण है। 2024 के चुनावी नतीजे ने बीजू जनता दल (बीजद) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाय॰एस॰आर॰सी॰पी॰) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक कठोर वास्तविकता को उजागर कर दिया है - भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ उनकी छेड़खानी की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है, जिससे उनकी राजनीतिक स्वायत्तता खत्म हुई है और उन्हें महत्वपूर्ण चुनावी झटके लगे हैं (जेंकिंस 2024, पृष्ठ संख्या-94)। ओडिशा में, बीजू जनता दल की भाजपा के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की बातचीत अंततः सीट बंटवारे के विवादों पर टूट गई। शुरुआती चर्चाओं के बावजूद, 147 विधानसभा सीटों में से 100 से

अधिक पर चनाव लड़ने की बीजेडी की मांग को भाजपा ने अस्वीकार्य माना. जिसने लोकसभा सीटों का बड़ा हिस्सा मांगा। इस विफल वार्ता ने बीजेडी को कमजोर बना दिया, और भाजपा ने इस कलह का फायदा उठाया, राज्य में महत्वपूर्ण लाभ हासिल किया। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाब् नायड् के नेतृत्व वाली टीडीपी ने अपने अभियान को वाईएसआरसीपी सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर केंद्रित किया, मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित किया और वाईएसआरसीपी के भाजपा के साथ गठबंधन के नुकसान को उजागर किया । बीजद और वाईएसआरसीपी दोनों ने क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय गठबंधनों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी रणनीति उल्टी पड़ गई। भाजपा के प्रभुत्व और रणनीतिक अभियान ने इन क्षेत्रीय दिग्गजों को प्रभावी रूप से हाशिए पर डाल दिया, यह दर्शाता है कि बड़े राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन दोधारी तलवार हो सकता है। ये परिणाम क्षेत्रीय दलों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक को भी रेखांकित करते हैं - मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने और चुनावी सफलता के लिए राजनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने दिखाया है कि क्षेत्रीय दलों को भारत के गतिशील राजनीतिक परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता और प्रभाव बनाए रखने के लिए अस्थिर राष्ट्रीय गठबंधनों पर अपने घटकों की ज़रूरतों की प्राथमिकता देनी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में क्षेत्रवाद, जो मुख्यतः देश की विविधता से उपजता है, सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता, और आर्थिक विकास की माँग के माध्यम से प्रकट होता है। क्षेत्रीय आकांक्षाएँ भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के ताने-बाने पर विभाजनकारी और एकीकरणकारी, दोनों तरह के प्रभाव डालने की क्षमता रखती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय राजनीति की बदलती गतिशीलता का एक स्पष्ट संकेतक है, जहाँ क्षेत्रीय दल न केवल सहयोगी है बल्कि वर्तमान गठबंधन का सूत्रधार और बुनियाद भी है। यह बदलाव जनता की विविध आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हुए अधिक समावेशी और क्षेत्रीय प्रतिनिधि शासन का सूत्रपात किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रमाण है। इस प्रचलित धारणा के विपरीत 2014 के बाद से भाजपा के एकदलीय बहुमत की जीत क्षेत्रीय दलों के पतन का प्रतीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम ने राजनीति में क्षेत्रीय राजनीति और क्षेत्रीय दलों की स्थायी महत्व को रेखांकित किया है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने लोकसभा में लगभग 293 सीटें हासिल कीं। इसके विपरीत, विपक्षी गठबंधन, इंडिया ब्लॉक ने 232 सीटें हासिल कीं। एनडीए के बहमत के बावजुद, सरकार का गठन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ियों- बिहार से नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) के समर्थन पर टिका है।

यह गठबंधन क्षेत्रीय दलों के निरंतर प्रभाव और भविष्य की राजनीतिक गितशीलता को आकार देने में उनकी निर्णायक भूमिका को रेखांकित करता है। 2024 के चुनावों में दो उल्लेखनीय राजनीतिक ताकतों का पतन भी हुआ। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (बीजद), जिसने दो दशकों से अधिक समय तक ओडिशा पर अपना दबदबा बनाए रखा था, को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) को एक बड़ा झटका लगा। विपक्षी मोर्चे पर, सबसे बड़ी विपक्षी इकाई के रूप में कांग्रेस पार्टी ने पिछले दो चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। हालाँकि, क्षेत्रीय दलों की उल्लेखनीय सफलताओं को उजागर करना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी (सपा) ने शानदार जीत हासिल की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गित को रोक दिया और क्षेत्रीय राजनीति के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित किया। पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भाजपा के आक्रामक अभियान का डटकर सामना किया। भ्रष्टाचार के आरोपों और केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा शीर्ष नेताओं की कैद जैसी गंभीर चुनौतियों

का सामना करने के बावजूद, ममता बनर्जी भाजपा लहर को रोकने और अपना गढ़ बचाए रखने में सफल रहीं। जैसे-जैसे क्षेत्रीय दल अपना प्रभाव स्थापित कर रहे हैं, राष्ट्रीय आख्यान को इन निर्णायक ताकतों के अनुकूल ढलना होगा। इसलिए, 2024 के लोकसभा चुनाव न केवल क्षेत्रीय दलों के महत्व की पृष्टि करते हैं, बिल्क आने वाले वर्षों में एक अधिक जिंटल और बहुआयामी राजनीतिक क्षेत्र का भी संकेत देते हैं। राष्ट्रीय नीतियों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है, जिसने देश के शासन को आकार देने में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिलने के साथ, दोनों राष्ट्रीय दलों में से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इस परिदृश्य में नीतीश कुमार और एन. चंद्रबाबू नायडू जैसे क्षेत्रीय नेता अपरिहार्य किंगमेकर के रूप में सुर्खियों में आ गए हैं।

वर्तमान समय में राजनीतिक विश्लेषकों का अभिमत है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक हालात के तहत एकदलीय बहुमत की संभावना कुछ दशकों तक देखने को नहीं मिल सकता है। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन राजनीति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन बना कर रखता है जिसकी बहुत ज़रूरत राज्यों को है।

संदर्भ सूची

- पाई, सुधा (1990), भारत में क्षेत्रीय दल और राजनीति का उभरता स्वरूप, भारतीय राजनीति विज्ञान जर्नल, अंक-51, खंड-3, पृष्ठ संख्या-393-415।
- ब्लारेल, निकोलस (2019), "गठबंधन की राजनीति और भारतीय विदेश नीति का निर्माण: एक नया शोध कार्यक्रम", इंडिया रिव्यू, अंक-5, खंड-18, पृष्ठ संख्या-582-595।
- 3. रूपारेलिया, संजय (2015), विभाजित हम शासन करते हैं: आधुनिक भारत में गठबंधन की राजनीति, लंदन : ऑक्सफ़ोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।
- फ़ारूक़ी, अदनान और श्रीधरन, ई (2014), "क्या भारतीय राजनीति में गठबंधन युग समाप्त हो गया है?", कॉमनवेल्थ जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड पॉलिसी स्टडीज, अंक-6, खंड-103, पृष्ठ संख्या-557-569
- तुम्माला, कृष्णा के。 (2009), "भारत में गठबंधन की राजनीति: 2004-2009", एशियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अंक-3, खंड-17, पृष्ठ संख्या-323-348।
- 6. येरंकर, श्रीराम (2015), "भारत में गठबंधन की राजनीति", भारतीय राजनीति विज्ञान जर्नल, अंक-3, खंड-76, पृष्ठ संख्या-402-406।
- चंदर, एन. जोस (2004), गठबंधन की राजनीति: भारतीय अनुभव, नई दिल्ली: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी।
- मैकमिलन, एलिस्टैयर (2014), भारत में राजनीतिक दलीय गठबंधनों और गठबंधनों के कारण और राष्ट्रीय एकता पर उनका प्रभाव, जर्नल ऑफ़ अफ़्रीकन इलेक्शन, अंक-1, खंड-13, पृष्ठ संख्या-1-12।
- खान, एमजी (2003), भारत में गठबंधन सरकार और संघीय व्यवस्था, भारतीय राजनीति विज्ञान जर्नल, अंक-3, खंड-64, पृष्ठ संख्या-167-190
- 10. कैलाश, के॰के॰ (2014), "भारत में गठबंधन प्रणाली और गठबंधनों के भीतर खेलों का संस्थागतकरण" (1996-2014), सेज पब्लिकेशन, अंक-2, खंड-2, पृष्ठ संख्या-1-22
- 11. के.के., कैलाश (2014), नई दलीय व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और गठबंधन निर्माण, नई दिल्ली: एकेडिंमक फाउंडेशन।
- 12. ई., श्रीधरन (2004), 2004 के आम चुनावों में चुनावी गठबंधन: सिद्धांत और साक्ष्य, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अंक-39, खंड-51, पृष्ठ संख्या-5418–5425।
- कैलाश, के.के. (2014), नई दलीय व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और गठबंधन निर्माण, नई दिल्ली: एकेडिमिक फाउंडेशन।

- 14. एल्लप्पा, संगीता (2020), भारत में गठबंधन सरकार: राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, थर्ड कॉन्सेप्ट, अंक-1, खंड-1, पृष्ठ संख्या-26-31।
- 15. अनुराग, तेनाली (2022), गठबंधन सरकार और भारत के संघीय संरचना पर इसका प्रभाव, इंडियन जर्नल ऑफ़ लॉ और लीगल रिसर्च, अंक-4, खंड-2, पृष्ठ संख्या-1-15।
- राथर, तारिक (2020), भारत में गठबंधन राजनीति का राजनीतिक विकास, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, अंक-3, खंड-11, पृष्ठ संख्या-1-14।
- 17. शिंदे, सुनील वी. (2017), भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की राजनीति-एक विश्लेषण, भारतीय राजनीति विज्ञान जर्नल, अंक-4, खंड-78, पृष्ठ संख्या-483-486।
- 18. ई श्रीधरन (2017), समीक्षा: कथात्मक दृष्टिकोण से गठबंधन राजनीति का विश्लेषण, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, अंक-9, खंड-54, पृष्ठ संख्या-55-58।
- 19. जेंकिंस, रॉब (2024), गठबंधन राजनीति और मोदी सरकार 3.0 : समकालीन इतिहास और सिद्धांत से संकेत, इंडियन पोलिटिक्स और पॉलिसी जर्नल, अंक-4, खंड-2, पृष्ठ संख्या-93-120।
- 20. देब, पापिया और सेनगुप्ता, पीके (2009), गठबंधन की राजनीति और भारत के संघीय शासन के बदलते परिप्रेक्ष्य, भारतीय राजनीति विज्ञान जर्नल, अंक-2, खंड-70, पृष्ठ संख्या-387-407।
- 21. कुमार, मनोज (2017), भारत में गठबंधन की राजनीति: राजनीतिक गठबंधनों का इतिहास और विश्लेषण, सरदार पटेल विश्वविद्यालय-शांति एवं संघर्ष अध्ययन केंद्र, अंक-1, खंड-1, पृष्ठ संख्या-1-16।
- 22. बर्थवाल, सीपी (2012), भारत में गठबंधन सरकारें, भारतीय राजनीति विज्ञान जर्नल, अंक-1, खंड-73, पृष्ठ संख्या-9-20।